

मुकदमों का विवरण

एसएमटी। रूपा सोनी बनाम

कमलनारायण सोनी

(सिविल अपील सं. 2023 की 5700) सितंबर 06, 2023

[संजीव खन्ना और एम. एम. सुंदरेश, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: जब दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे और डेढ़ दशक से अलग रह रहे थे, तो क्या निचली अदालत और उच्च न्यायालय को तलाक की डिक्री को अस्वीकार करने में अति-तकनीकी और पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने के लिए न्यायसंगत ठहराया गया था।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955-अपीलार्थी-पत्नी ने यू/एस के तहत शिकायत दर्ज की। 498 आई. पी. सी. और एस. एस. का ए। 3 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 का 4-प्रत्यर्थी-पति ने अपीलार्थी-पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाया था-तलाक के लिए याचिका-निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने तलाक के आदेश को अस्वीकार कर दिया-स्वामित्व:

आयोजित किया गया: डेढ़ दशक से, पक्षकार अलग-अलग रह रहे हैं-विवाह अब और नहीं टिकता है, और रिश्ते को अन्यथा तलाक की औपचारिक डिक्री के अलावा समाप्त कर दिया गया था-निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने तलाक की डिक्री को अस्वीकार करने में एक अति-तकनीकी और पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया-ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी-पति अपीलकर्ता-पत्नी के साथ रहने के लिए तैयार हैं-उसके खिलाफ उसके द्वारा लगाए गए आरोप उतने ही गंभीर हैं जितने कि उसके द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोप-दोनों पक्ष दूर चले गए हैं और अपने-अपने जीवन में बस गए हैं-उनके एक साथ रहने के बिना केवल स्थिति की पीड़ा को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है-निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय ने दरकिनार कर दिया है। [पैरा 17, 19, 20]

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 -एस. 13 (1) (आई. ए.)-क्रूरता:

आयोजित किया गया: 1955 के अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत 'क्रूरता' शब्द का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, और इसलिए, न्यायालय को इसे उदारता और प्रासंगिक रूप से लागू करने के लिए बहुत व्यापक विवेकाधिकार देता है-एक मामले में क्रूरता क्या है 872

871

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

हो सकता है कि दूसरे के लिए समान न हो-उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर लागू किया जाना चाहिए।[पैरा 5]

तलाक-बिपिन चंदर जयसिंहभाई शाह बनाम प्रभावती-निर्णय का स्पष्टीकरण:

आयोजित किया गया:बिपिन चंदर जयसिंहभाई शाह बनाम प्रभावती, 1956 एस. सी. आर. 838 में दिया गया निर्णय स्पष्ट किया गया है, यह अभिनिर्धारित करने का प्रस्ताव नहीं है कि क्रूरता का आरोप लगाने वाले वैवाहिक मामले में याचिकाकर्ता से आवश्यक सबूत उचित संदेह से परे है, और संभावना की प्रधानता का नहीं है-बिपिन चंदर में न्यायालय त्याग के मामले पर विचार कर रहा था, और इसलिए, उस व्यक्ति पर अधिक जिम्मेदारी डाली गई थी जो इस पर जोर देता है-अदालत निर्णय नहीं ले रही है और निर्णय नहीं ले रही है, जब तलाक के लिए याचिका एक नागरिक उपाय है। [पैरा 12]

हिंदू विवाह अधिनियम, **1955** -धारा **23**-कार्यवाहियों में डिक्ली -

चर्चा की।[पैरा 13,14]

तलाक-सामाजिक-आर्थिक कलंक और महिला से जुड़े मुद्दे-चर्चा की गई।[पैरा 8]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन 2023 (6) स्केल 402-इसके बाद।विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल (2012) 7 एससीसी 288:[2012] 7 एससीआर 607; बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे और एक अन्य

(2014) 1 एससीसी 188:[2013] 10 एससीआर 259; एन. जी. दास्ताने बनाम श्रीमती एस. दास्ताने (1975) 2 एस. सी. सी. 326:[1975] 3 एस. सी. आर. 967; शिवशंकरन बनाम संधिमीनल 2021

(10) स्केल 477; श्रीटी होशी डोलिकुका बनाम होशियाम शावाक्षा डोलिकुका

(1982) 2 एससीसी 544:[1983] 1 एस. सी. आर. 49-निर्भर।

रेनॉल्ड राजामणि और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य (1982) 2 एस. सी. सी. 474; डॉ. बिपिन चंदर जयसिंहभाई शाह बनाम प्रभावती 1956 एस. सी. आर. 838; लक्ष्मण उत्तमचंद कृपलानी बनाम मीना उर्फ मोटा (1964) 4 एस. सी. आर.

331 – संदर्भित किया गया।

873

एसएमटी। रूपा सोनी बनाम कमलनारायण सोनी 874

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील सं. 5700/2011 के एफ. ए. No.115 में बिलासपुर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

दुष्यंत पाराशर, दिनेश पांडे, मनु पाराशर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

शांतनु सागर, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

एम. एम. सुंदरेश, जे.

छुट्टी दे दी गई।

2. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (इसके बाद 1955 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13 (1) और 13 (1 ए) तलाक देने के लिए विभिन्न आधार प्रदान करती है:

“13. तलाक हो गया।—(1) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न कोई भी विवाह, पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, इस आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा भंग किया जा सकता है कि दूसरा पक्ष -

((i) विवाह सम्पन्न हो जाने के बाद, अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक यौन संबंध बनाए हैं; या (i) विवाह संपन्न होने के बाद, याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है; या

( (i) याचिकाकर्ता को याचिका प्रस्तुत करने से तुरंत पहले कम से कम दो साल की निरंतर अवधि के लिए छोड़ दिया है; या

( (ii) दूसरे धर्म में परिवर्तन करके हिंदू होना बंद कर दिया है; या

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

( iii) असाध्य रूप से अस्वस्थ दिमाग का रहा है, या इस तरह के मानसिक विकार से लगातार या बीच-बीच में इस हद तक पीड़ित रहा है कि याचिकाकर्ता से प्रतिवादी के साथ रहने की उचित रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती है।

स्पष्टीकरण।—इस खंड में, (ए) "मानसिक विकार" अभिव्यक्ति का अर्थ है मानसिक बीमारी, मन का अवरुद्ध या अपूर्ण विकास, मनोरोगी विकार या कोई अन्य विकार या मन की अक्षमता और इसमें स्किज़ोफ्रेनिया शामिल है;

( बी) "मनोरोगी विकार" अभिव्यक्ति का अर्थ है मन का एक निरंतर विकार या अक्षमता (चाहे बुद्धि की उप-सामान्यता सहित हो या नहीं) जिसके परिणामस्वरूप दूसरे पक्ष की ओर से असामान्य रूप से आक्रामक या गंभीर रूप से गैर-जिम्मेदाराना आचरण होता है, और क्या इसके लिए चिकित्सा उपचार की आवश्यकता है या नहीं; या

xxx xxx xxx

( v) संचारी रूप में यौन रोग से पीड़ित रहा है; या

( vi) किसी भी धार्मिक व्यवस्था में प्रवेश करके दुनिया का त्याग कर दिया है; या (vii) उन व्यक्तियों द्वारा सात साल या उससे अधिक की अवधि के लिए जीवित होने के रूप में नहीं सुना गया है, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सुना होगा, अगर वह पक्ष जीवित होता;

[ स्पष्टीकरण।—इस उप-धारा में, "त्याग" पद का अर्थ है याचिकाकर्ता का दूसरे पक्ष द्वारा उचित कारण के बिना और सहमति के बिना या ऐसे पक्ष की इच्छा के खिलाफ विवाह के लिए त्याग, और इसमें दूसरे पक्ष द्वारा विवाह के लिए याचिकाकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा शामिल है, और इसके व्याकरणिक बदलाव और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

(1 क) विवाह का कोई भी पक्ष, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में संपन्न हो, इस आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह को भंग करने के लिए याचिका भी पेश कर सकता है-875

एसएमटी। रूपा सोनी बनाम कमलनारायण सोनी [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 876

( (i) जिस कार्यवाही में वे पक्षकार थे, उस कार्यवाही में न्यायिक अलगाव के लिए डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए विवाह के पक्षों के बीच सहवास फिर से शुरू नहीं हुआ है; या

( (ख) विवाह के पक्षकारों के बीच वैवाहिक अधिकारों की किसी कार्यवाही में, जिसमें वे पक्षकार थे, वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए कोई पुनर्स्थापना नहीं हुई है।”3. 1976 के संशोधन अधिनियम (1976 का अधिनियम 68) ने तलाक के अनुदान को उदार बनाने के लिए धारा 13 और धारा 13 ए आदि के खंड (आई. ए.) और (आई. बी.) पेश किए थे। जब विधेयक पेश किया गया था, तो उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नलिखित शब्दों में कारणों को स्पष्ट रूप से बताता है:

“विवाह विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण:

“(1) तलाक से संबंधित प्रावधानों को उदार बनाना;

(2) अधिनियम के तहत कार्यवाही के त्वरित निपटान को सक्षम करने के लिए; और

(3) अधिनियमों के पारित होने के बाद सामने आई कुछ विसंगतियों और बाधाओं को दूर करना।”

4. विधेयक से पहले, विधि और न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री ने 17.01.1974 पर भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष को एक संदेश संबोधित किया, जिसमें तलाक की कार्यवाही को उदार बनाने की दिशा में उनके विचार मांगे गए, जिसके परिणामस्वरूप भारत के विधि आयोग की 59 वीं रिपोर्ट आई। 1976 के संशोधन अधिनियम ने 1955 के अधिनियम की धारा 13 में कुछ और खंड जोड़ते हुए काफी संशोधन किया। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि संसद का इरादा बहुत स्पष्ट है, जो तलाक के प्रावधान को उदार बनाना है, जबकि अलग हो चुकी पत्नी के लिए आवश्यक सुरक्षा के प्रति सचेत है। 1955 के अधिनियम की धारा 13 (1) के उपखंडों को लागू करते समय, तलाक की मंजूरी के लिए याचिका का विरोध करने वाले पति या पत्नी की स्थिति की उचित समझ होनी चाहिए क्योंकि सामाजिक व्यवस्था, शैक्षिक योग्यता, वित्तीय स्थिति, रोजगार, जाति, समुदाय, आयु और स्थान जैसे कारकों के आधार पर परिणाम और प्रभाव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

5. 1955 के अधिनियम की धारा 13 (1) (आई. ए.) के तहत 'क्रूरता' शब्द का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, और इसलिए, न्यायालय को इसे उदारता और प्रासंगिक रूप से लागू करने के लिए बहुत व्यापक विवेकाधिकार देता है। एक मामले में जो क्रूरता है वह दूसरे के लिए समान नहीं हो सकती है। जैसा कि कहा गया है, उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर लागू किया जाना चाहिए।

### 6. विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरला विश्वनाथ अग्रवाल, (2012) 7

एस. सी. सी. 288 यह न्यायालय पर्याप्त रूप से निर्धारित करता है: “22. “क्रूरता” अभिव्यक्ति का मानव आचरण या मानव व्यवहार के साथ एक अविभाज्य संबंध है। यह हमेशा उस सामाजिक स्तर या परिवेश पर निर्भर करता है जिसमें पक्ष शामिल होते हैं, उनके जीवन के तरीके, संबंध, स्वभाव और भावनाएं जो उनकी सामाजिक स्थिति से प्रभावित होती हैं।

xxx xxx xxx

25. ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने शोभा रानी मामले [(1988) 1 एस. सी. सी. 105 में कहा: 1988 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 60] आधुनिक समय में जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन और वैवाहिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में समुद्री परिवर्तन के बारे में। यह देखा गया है कि: (एस. सी. सी. पी. 108, पैरा 5) “5. ... जब कोई जीवनसाथी जीवन या संबंधों में साथी द्वारा क्रूरता के व्यवहार के बारे में शिकायत करता है, तो अदालत को जीवन में मानक की तलाश नहीं करनी चाहिए। एक मामले में क्रूरता के रूप में कलंकित तथ्यों का एक समूह दूसरे मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। कथित क्रूरता काफी हद तक इस बात पर निर्भर कर सकती है कि पक्ष किस प्रकार के जीवन के आदी हैं या उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। यह उनकी संस्कृति और मानवीय मूल्यों पर भी निर्भर हो सकता है जिन्हें वे महत्व देते हैं।”

26. शोभा रानी मामले में उनके प्रभुत्व [(1988) 1 एस. सी. सी. 105:1988 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 60] ने शेल्डन बनाम शेल्डन [1966 पी 62:(1966) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 993: (1966) 2 सभी ई. आर. 257 (सी. ए.)] जिसमें लॉर्ड डेनिंग ने कहा था, "क्रूरता की श्रेणियां बंद नहीं हैं।" इसके बाद पीठ ने आगे कहा: (शोभा रानी मामला [(1988) 1 एस. सी. सी. 105:1988 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 60], एस. सी. सी. पी. 109, पैरा 5-6) "5. प्रत्येक मामला अलग-अलग हो सकता है। हम उन मनुष्यों के आचरण से निपटते हैं जो आम तौर पर समान नहीं होते हैं। 877 में से

एसएमटी। रूपा सोनी बनाम कमलनारायण सोनी [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 878

मनुष्यों के आचरण की कोई सीमा नहीं है जो क्रूरता का कारण बन सकता है। मानव व्यवहार, क्षमता या शिकायत किए गए आचरण को सहन करने में असमर्थता के आधार पर किसी भी मामले में नए प्रकार की क्रूरता सामने आ सकती है। यही क्रूरता का अद्भुत क्षेत्र है।

6. इन प्रारंभिक टिप्पणियों का उद्देश्य इस बात पर जोर देना है कि वैवाहिक मामलों में न्यायालय पारिवारिक जीवन में आदर्शों से संबंधित नहीं है। अदालत को केवल संबंधित पति-पत्नी को समझना होगा क्योंकि प्रकृति ने उन्हें बनाया है, और उनकी विशेष शिकायत पर विचार करना होगा। जैसा कि लॉर्ड रीड ने गोलिंस बनाम गोलिंस [1964 ए. सी. 644:(1963) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 176:(1963) 2 सभी ई. आर. 966 (एच. एल.)]: (सभी ई. आर. पी. 972 जी-एच)

‘... वैवाहिक सम्बन्धों में हम वस्तुनिष्ठ मानकों के साथ काम नहीं कर रहे हैं, उचित पुरुष (या उचित महिला) के मानकों से नीचे गिरना वैवाहिक संबंध नहीं है। हम इस पुरुष या इस महिला के साथ काम कर रहे हैं।’ ”

xxx xxx xxx

32. समर घोष बनाम जया घोष [(2007) 4 एस. सी. सी. 511] में, इस न्यायालय ने पिछले निर्णयों का सर्वेक्षण करने और क्रूरता की अवधारणा का उल्लेख करने के बाद, जिसमें अंग्रेजी, अमेरिकी, कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई मामलों में मानसिक क्रूरता शामिल है, कहा है: (एस. सी. सी. पीपी. 545-46, पैरा 99-100)

“99. ... मानव मन अत्यंत जटिल है और मानव व्यवहार भी उतना ही जटिल है। इसी तरह मानव चतुराई की कोई सीमा नहीं है, इसलिए, पूरे मानव व्यवहार को एक निश्चितता में आत्मसात करना लगभग असंभव है। एक मामले में जो क्रूरता है वह दूसरे मामले में क्रूरता नहीं हो सकती है। क्रूरता की अवधारणा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में उसकी परवरिश, संवेदनशीलता के स्तर, शैक्षिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, वित्तीय स्थिति, सामाजिक स्थिति, रीति-रिवाज, परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं, मानवीय मूल्यों और उनकी मूल्य प्रणाली के आधार पर भिन्न होती है।

100. इसके अलावा, मानसिक क्रूरता की अवधारणा स्थिर नहीं रह सकती; यह समय के साथ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मूल्य के माध्यम से आधुनिक संस्कृति के प्रभाव के साथ बदलने के लिए बाध्य है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

प्रणाली आदि। अब जो मानसिक क्रूरता हो सकती है वह समय बीतने के बाद मानसिक क्रूरता नहीं रह सकती है या इसके विपरीत भी। वैवाहिक मामलों में मानसिक क्रूरता को निर्धारित करने के लिए कभी भी कोई स्ट्रैटिजिक फॉर्मूला या फिएड मापदंड नहीं हो सकते हैं। मामले में निर्णय लेने का विवेकपूर्ण और उचित तरीका इसके विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर इसका मूल्यांकन करना होगा।”

(जोर दिया गया)

7. हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि व्यक्तिपरकता के एक तत्व को लागू किया जाना चाहिए, हालांकि जो क्रूरता का गठन करता है वह उद्देश्यपूर्ण है। इसलिए, किसी दिए गए मामले में एक महिला के लिए क्रूरता एक पुरुष के लिए क्रूरता नहीं हो सकती है, और जब हम एक ऐसे मामले की जांच करते हैं जिसमें एक पत्नी तलाक चाहती है तो अपेक्षाकृत अधिक लोचदार और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। 1955 के अधिनियम की धारा 13 (1) दोनों पक्षों के कहने पर तलाक देने के लिए रूपरेखा और कठोरता निर्धारित करती है। ऐतिहासिक रूप से, तलाक का कानून मुख्य रूप से गलती सिद्धांत के आधार पर एक रूढ़िवादी कैनवास पर बनाया गया था। सामाजिक दृष्टिकोण से वैवाहिक पवित्रता का संरक्षण एक प्रचलित कारक माना जाता था। एक स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण को अपनाने के साथ, अलग होने या विवाह के विघटन के आधार को अक्षांशवाद के साथ समझा गया है।

8. वैवाहिक कानूनों के इस तरह के उदार निर्माण के बावजूद, तलाक या अलगाव के कारण एक महिला से जुड़े सामाजिक-आर्थिक कलंक और मुद्दे उठाए जाते हैं। न्यायमूर्ति O.Chinnappa रेड्डी, अपनी सहमति वाली राय में

रेनॉल्ड राजामणि और एक अन्य बनाम भारत संघ और एक अन्य, (1982) 2

एस. सी. सी. 474 (पैराग्राफ 14 देखें), ने वैवाहिक संबंधों में महिलाओं की स्थिति और तलाक के मद्देनजर महिला पति या पत्नी द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक और आर्थिक असमानताओं पर ध्यान दिया। परिणामस्वरूप कलंक सामाजिक पुनर्एकीकरण में बाधा डालता है, जिससे एक महिला तलाकशुदा सामाजिक और आर्थिक रूप से निर्भर हो जाती है। न्यायालयों को एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और स्थिति, मामले और इसमें शामिल व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए कुछ हद तक सामाजिक-आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कमजोर पक्ष पर मानसिक और कभी-कभी शारीरिक आघात को कायम रखने की संभावनाओं को रोकने के लिए

तथ्यों का एक सहानुभूतिपूर्ण और प्रासंगिक निर्माण अपनाया जा सकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अदालतें समानता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होंगी और पक्षों के अधिकारों को संतुलित करने पर विचार कर सकती हैं। न्यायालय को इन प्रावधानों को लागू करते समय सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं के साथ-साथ पक्षों की स्थिति और पृष्ठभूमि से अवगत 'सामाजिक-संदर्भ सोच' को अपनाना चाहिए।

879

एसएमटी। रूपा सोनी बनाम कमलनारायण सोनी [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 880

9. "सामाजिक न्याय निर्णय" की इस अवधारणा को विस्तार से समझाया गया है।

बादशाह बनाम उर्मिला बादशाह गोडसे और एक अन्य मामले में इस अदालत द्वारा निपटा गया,

**(2014) 1 एससीसी 188:**

“14. हाल ही में, इस दिशा में, इस बात पर जोर दिया गया है कि अदालतों को "सामाजिक न्याय निर्णय" में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाने होंगे, जिसे "सामाजिक संदर्भ निर्णय" के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि केवल "प्रतिकूल दृष्टिकोण" बहुत उपयुक्त नहीं हो सकता है। समाज में कमजोर समूहों को विशेष सुरक्षा और लाभ प्रदान करने वाले कई सामाजिक न्याय कानून हैं। प्रो. माधव मेनन ने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है:

“इसलिए, यह सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि 'सामाजिक संदर्भ न्यायनिर्णयन' अनिवार्य रूप से समानता न्यायशास्त्र का अनुप्रयोग है जैसा कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अदालतों के समक्ष प्रस्तुत असंख्य स्थितियों में विकसित किया गया है जहां असमान पक्षों को प्रतिकूल कार्यवाही में खड़ा किया जाता है और जहां अदालतों को समान न्याय देने के लिए कहा जाता है। असमान स्थिति में गरीबों की अक्षमताओं को बढ़ाने वाली सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के अलावा, प्रतिकूल प्रक्रिया स्वयं कमजोर पक्ष के नुकसान के लिए काम करती है। ऐसी स्थिति में, न्यायाधीश को न केवल शामिल पक्षों की असमानताओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, बल्कि कमजोर पक्ष के प्रति सकारात्मक झुकाव भी होना चाहिए यदि असंतुलन के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता नहीं होती है। यह परिणाम सामाजिक संदर्भ निर्णय या सामाजिक न्याय निर्णय द्वारा प्राप्त किया जाता है।” [ 12 अक्टूबर, 2005 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में "सामाजिक संदर्भ में कानूनी शिक्षा" पर दिया गया मुख्य भाषण, जो एच. टी. पी. पर उपलब्ध है://वेब.अभिलेख।ओआरजी/वेब/20061210031743/एचटीटीपी:/डब्ल्यू. डब्ल्यू. न्लुजोधपुर। एसी।इन/सीरिपोर्ट्स।एच. टी. एम. [आखिरी बार 25-12-2013 पर देखा गया]

15. रखरखाव का प्रावधान निश्चित रूप से इस श्रेणी में आता है जिसका उद्देश्य निराश्रितों को सशक्त बनाना और सामाजिक न्याय या व्यक्ति की समानता और गरिमा प्राप्त करना है। इस प्रावधान के तहत मामलों से निपटने के दौरान, "प्रतिकूल" मुकदमेबाजी से सामाजिक संदर्भ में निर्णय लेने के दृष्टिकोण में बदलाव समय की आवश्यकता है।

16. कानून लोगों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। यह व्यवहार के प्रतिमान निर्धारित करता है। यह समाज के मूल्यों को दर्शाता है। की भूमिका

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

न्यायालय समाज में कानून के उद्देश्य को समझना और कानून को अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करना है। लेकिन समाज का कानून एक जीवित जीव है। यह एक दी गई तथ्यात्मक और सामाजिक वास्तविकता पर आधारित है जो लगातार बदल रही है। कभी-कभी कानून में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन से पहले होता है और इसका उद्देश्य इसे प्रोत्साहित करना भी होता है। हालाँकि, ज्यादातर मामलों में, कानून में परिवर्तन सामाजिक वास्तविकता में परिवर्तन का परिणाम है। वास्तव में, जब सामाजिक वास्तविकता बदलती है, तो कानून को भी बदलना चाहिए। जिस तरह सामाजिक वास्तविकता में परिवर्तन जीवन का नियम है, उसी तरह सामाजिक वास्तविकता में परिवर्तन के प्रति प्रतिक्रिया कानून का जीवन है। यह कहा जा सकता है कि कानून का इतिहास समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार कानून को अपनाने का इतिहास है। संवैधानिक और वैधानिक दोनों व्याख्याओं में, न्यायालय को कानून के व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ उद्देश्यों के बीच उचित संबंध निर्धारित करने में विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

xxx xxx xxx

18. कानून के दुभाषिया के रूप में अदालत से अपेक्षा की जाती है कि वह त्रुटियों की आपूर्ति करे, अनिश्चितताओं को ठीक करे और स्वतंत्र निर्णय की एक विधि के माध्यम से परिणामों को न्याय के साथ सुसंगत बनाए-लिब्रे रिसर्च साइंटिफिक क्यू यानी "फ्री साइंटिफिक सी रिसर्च"। हमारी राय है कि एक गैर-खंडन योग्य धारणा है कि विधायिका ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 जैसे प्रावधान करते हुए, सद्भावना से अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए, हमेशा ऐसी परिस्थितियों में महिला को "पत्नी" बनने से राहत देने का इरादा रखा था। लैंगिक न्याय से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेते समय इस दृष्टिकोण की विशेष रूप से आवश्यकता है। हमारे पास पहले से ही इस संबंध में अनुकरणीय प्रभाव के उदाहरण हैं। शाह बानो से यात्रा [मोहम्मद।

अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम, (1985) 2 एससीसी 556:1985 एससीसी

(क्रि) 245:ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 945] से शबाना बानो [शबाना बानो बनाम इमरान खान, (2010) 1 एस. सी. सी. 666:(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. वी.) 216:(2010) 1 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 873:ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 305] मुस्लिम महिलाओं को रखरखाव के अधिकारों की गारंटी देना एक उत्कृष्ट उदाहरण है।”

(जोर दिया गया)

10. तलाक के लिए याचिका में बोझ के सवाल पर, सबूत का बोझ याचिकाकर्ता पर होता है। हालाँकि, संभावना की मात्रा उचित संदेह से परे नहीं है, बल्कि प्रधानता की है।

एसएमटी। रूपा सोनी बनाम कमलनारायण सोनी [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 882

11. डॉ. एन. जी. दास्ताने बनाम श्रीमती एस. दास्ताने, (1975) 2 एस. सी. सी. 326 में, यह

आयोजित किया गया था: “25. उचित संदेह से परे प्रमाण एक उच्च मानक द्वारा प्रमाण है जो आम तौर पर अर्ध-आपराधिक प्रकृति के मुद्दों की जांच से जुड़े आपराधिक परीक्षणों या परीक्षणों को नियंत्रित करता है। आपराधिक मुकदमे में विषय की स्वतंत्रता शामिल होती है जिसे केवल संभावनाओं की अधिकता पर नहीं खोया जा सकता है। यदि संभावनाएं इतनी अच्छी तरह से संतुलित हैं कि एक तर्कसंगत, अस्थिर नहीं, मन यह नहीं समझ सकता है कि जहां प्रमुखता निहित है, तो साबित किए जाने वाले तथ्य के अस्तित्व के बारे में संदेह उत्पन्न होता है और इस तरह के उचित संदेह का लाभ अभियुक्त को जाता है। विशुद्ध रूप से नागरिक प्रकृति के परीक्षणों में इस तरह के विचारों को आयात करना गलत है।

26. न तो अधिनियम की धारा 10, जो उन आधारों की गणना करती है जिन पर न्यायिक पृथक्करण के लिए याचिका प्रस्तुत की जा सकती है और न ही धारा 23, जो अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में डिफ्री पारित करने के लिए न्यायालय की अधिकारिता को नियंत्रित करती है, के लिए यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता को अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करना चाहिए। धारा 23 न्यायालय को डिफ्री पारित करने की शक्ति प्रदान करती है यदि यह धारा के खंड (ए) से (ई) में उल्लिखित मामलों पर "संतुष्ट" होती है। यह देखते हुए कि अधिनियम के तहत कार्यवाही अनिवार्य रूप से एक नागरिक प्रकृति की है, "संतुष्टि" शब्द का अर्थ "संभावनाओं की प्रधानता पर संतुष्टि" होना चाहिए और "उचित संदेह से परे संतुष्टि" नहीं होना चाहिए। धारा 23 दीवानी मामलों में सबूत के मानक को नहीं बदलती है।

27. वैवाहिक मामलों में सबूत के मानक के बारे में गलत धारणा शायद ऐसे मामलों में प्रतिवादी के आचरण के एक ढीले विवरण से उत्पन्न होती है जैसे कि "वैवाहिक संबंध" का गठन। एक पति या पत्नी के कार्य जो एक वैवाहिक संघ की अखंडता को खराब करने के लिए गिने जाते हैं, उनका एक सामाजिक महत्व होता है। शादी करना या न करना और यदि ऐसा है तो किससे, यह एक निजी मामला हो सकता है, लेकिन वैवाहिक संबंध तोड़ने की स्वतंत्रता नहीं है। विवाह की संस्था में समाज की हिस्सेदारी होती है और इसलिए गलती करने वाले पति या पत्नी को केवल चूककर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक चूककर्ता के रूप में माना जाता है। लेकिन यह सामाजिक दर्शन, हालांकि इसका विवाह के विघटन के आधार के रूप में स्वीकार किए जाने से पहले किसी आरोप के स्पष्ट प्रमाण की आवश्यकता पर असर पड़ सकता है, लेकिन वैवाहिक मामलों में सबूत के मानक पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है।”

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

12. उपरोक्त निर्णय को सम्मानजनक अनुमोदन के साथ उद्धृत करते हुए, हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि बिपिन चंदर जयसिंहभाई शाह बनाम प्रभावती 1,1956 एस. सी. आर. 838 में दिया गया निर्णय यह मानने का प्रस्ताव नहीं है कि वैवाहिक मामले में क्रूरता का आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता से आवश्यक सबूत उचित संदेह से परे है, और संभावना की प्रधानता का नहीं है। बिपिन चंदर (ऊपर) में न्यायालय त्याग के एक मामले पर विचार कर रहा था, और इसलिए, इसका दावा करने वाले व्यक्ति पर अधिक जिम्मेदारी डाली गई थी। जब तलाक के लिए याचिका एक नागरिक उपचार है, तब न्यायालय निर्णय नहीं ले रहा है और निर्णय नहीं ले रहा है।

13. यद्यपि 1955 के अधिनियम की धारा 23 (1) 2 क्रूरता के आधार पर तलाक याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा क्रूरता की क्षमा की बात करती है, और इस प्रकार तलाक की डिक्री के अनुकूल नहीं है, इसे वैवाहिक संबंध में एक पुरुष और महिला की स्थिति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, 1955 के अधिनियम की धारा 23 (1) राहत पाने के लिए दुरुपयोग और कानून के दुरुपयोग के मामलों की जांच करने के लिए सावधानी का एक शब्द है। विस्तार से, अपनी असहनीय स्थिति के कारण, एक पत्नी अपनी आवाज उठाने और अपनी असहमति व्यक्त करने की स्थिति में नहीं हो सकती है, जिसे निष्क्रिय सहमति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

1 इस निर्णय को इस न्यायालय की एक विशेष न्यायाधीश पीठ द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया है।

लक्ष्मण उतमचंद कृपलानी बनाम मीना उर्फ मोटा, (1964) 4 एस. सी. आर. 331 में, जो

यह 'पलायन' से संबंधित है, जबकि वर्तमान मामले में 'क्रूरता' शामिल है।

2 23. कार्यवाहियों में आदेश।— (1) इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, चाहे बचाव किया गया हो या नहीं, अगर अदालत को संतुष्ट किया जाता है कि -

(क) राहत देने के लिए कोई भी आधार मौजूद है और याचिकाकर्ता उन मामलों को छोड़कर जहां धारा 5 के उपखंड (क), उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट आधार पर राहत मांगी गई है, किसी भी तरह से ऐसी राहत के उद्देश्य से अपनी गलती या अक्षमता का लाभ नहीं उठा रहा है, और

(ख) जहां याचिका का आधार धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आधार है, वहां याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह से शिकायत किए गए कार्य या कार्यों में सहायक या मिलीभगत नहीं की है या माफी नहीं दी है, या जहां याचिका का आधार क्रूरता है, याचिकाकर्ता ने किसी भी तरह से क्रूरता को माफ नहीं किया है, और

(ख) जब आपसी सहमति के आधार पर तलाक की मांग की जाती है, तो ऐसी सहमति बल, धोखाधड़ी या अनुचित प्रवाह द्वारा प्राप्त नहीं की गई है, और

(ग) याचिका (धारा 11 के तहत प्रस्तुत याचिका नहीं होने के कारण) प्रतिवादी के साथ मिलीभगत में प्रस्तुत या मुकदमा नहीं चलाया जाता है, और

(घ) कार्यवाही शुरू करने में कोई अनावश्यक या अनुचित देरी नहीं हुई है, और

(ङ) कोई अन्य कानूनी आधार नहीं है कि राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए, और ऐसे मामले में, लेकिन अन्यथा नहीं, अदालत तदनुसार ऐसी राहत का आदेश देगी।

14. 1955 के अधिनियम की धारा 23 (2) 3 में कहा गया है कि न्यायालय अधिनियम के तहत कोई भी राहत देने से पहले, पहली बार में, जहां मामले की प्रकृति और परिस्थितियों में संभव हो, पक्षों के बीच सुलह करने का हर संभव प्रयास करेगा। परंतुक में कुछ ऐसे अपवाद दिए गए हैं जिनसे हम संबंधित नहीं हैं। इस पहलू का उल्लेख धारा 23 की उप-धारा (3) 4 में भी किया गया है। इन प्रावधानों का उद्देश्य और उद्देश्य लिंगों के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का लाभ उठाते हुए किसी भी पक्ष की जांच करना है, इस तथ्य को देखते हुए कि कई अवसरों पर तलाक एक समस्या का समाधान कर सकता है, लेकिन दूसरा तब पैदा करता है जब महिला सामाजिक और आर्थिक रूप से अलग हो जाती है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए,

हाल ही में इस न्यायालय ने शिवशंकरन बनाम संधिमीनल, **2021 (10)** स्केल मामले में 477, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला था जिन्हें तलाक देते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए:

“6. विधायी जनादेश की अनुपस्थिति के अलावा, तलाक की इस तरह की डिक्री का विरोध करने के लिए अक्सर जो आधार लिया जाता है, वह यह है कि विवाह की संस्था को अलग-अलग देशों में स्पष्ट रूप से समझा जाता है। हिंदू कानून के तहत, यह चरित्र में पवित्र है और इसे दो लोगों का एक शाश्वत मिलन माना जाता है-भारत में एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह के बढ़ते महत्व को देखते हुए, बड़े पैमाने पर समाज तलाक को स्वीकार नहीं करता है। या कम से कम, तलाक की डिक्री के बाद महिलाओं के लिए सामाजिक स्वीकृति बनाए रखना कहीं अधिक कठिन पंथ है। यह, आर्थिक गारंटी देने में कानून की विफलता के साथ जोड़ा गया है

3 धारा 23 (2)-इस अधिनियम के तहत कोई राहत देने के लिए आगे बढ़ने से पहले, प्रत्येक मामले में जहां संभव हो, पक्षकारों के बीच सुलह करने के लिए हर संभव प्रयास करना न्यायालय का कर्तव्य होगा।

बशर्ते कि इस उप-धारा में निहित कुछ भी ऐसी किसी कार्यवाही पर लागू नहीं होगा जिसमें धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ii), खंड (iii), खंड (iv), खंड (v), खंड (vi) या खंड (vii) में विनिर्दिष्ट किसी भी आधार पर राहत मांगी गई हो।

4 धारा 23 (3)-ऐसा सुलह कराने में न्यायालय की सहायता करने के उद्देश्य से, न्यायालय, यदि पक्षकार ऐसा करना चाहते हैं या यदि न्यायालय ऐसा करना उचित और उचित समझता है, तो कार्यवाही को पंद्रह दिनों से अधिक की उचित अवधि के लिए स्थगित कर सकता है और मामले को पक्षकारों द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति या न्यायालय द्वारा नामित किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है, यदि पक्षकार किसी व्यक्ति का नाम लेने में विफल रहते हैं, इस बारे में न्यायालय को रिपोर्ट करने के निर्देश के साथ कि क्या सुलह हो सकता है और किया गया है, प्रभावी हो सकता है और कार्यवाही का निपटान करने में न्यायालय को रिपोर्ट पर उचित ध्यान देना होगा।

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

और विवाह टूटने की स्थिति में महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा; तलाक के आधार के रूप में अपरिवर्तनीय टूट को लागू करने के लिए विधायिका की अनिच्छा का कारण कहा जाता है-भले ही समय के साथ सामाजिक मानदंडों में बदलाव आया हो। सभी व्यक्ति एक ही सामाजिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, और इस प्रकार एक समान विधायी अधिनियम होने को अलग पंथ कहा जाता है। इन

परिस्थितियों में यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस तरह के आरक्षण के बावजूद अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है।

7. विवाह दो व्यक्तियों के बीच एक प्रतीत होने वाले सरल मिलन से अधिक है। एक सामाजिक संस्था के रूप में, सभी विवाहों के कानूनी, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव होते हैं। विवाह के मानदंड और इसकी वैधता के विभिन्न स्तर विवाह और तलाक कानूनों, प्रचलित सामाजिक मानदंडों और धार्मिक आदेशों जैसे कारकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कार्यात्मक रूप से, विवाहों को सामाजिक और सांस्कृतिक पूंजी के प्रसार के लिए एक स्थल के रूप में देखा जाता है क्योंकि वे संबंध संबंधों की पहचान करने, यौन व्यवहार को विनियमित करने और संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मदद करते हैं। परिवारों को समर्थन और मित्रता की आपसी अपेक्षा के विचार पर व्यवस्थित किया जाता है जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच अनुभव और स्वीकार किया जाना है। एक बार जब यह मित्रता टूट जाती है, तो परिणाम अत्यधिक विनाशकारी और कलंकित करने वाले हो सकते हैं। इस तरह के टूटने के प्राथमिक प्रभाव विशेष रूप से महिलाओं द्वारा महसूस किए जाते हैं, जिन्हें सामाजिक समायोजन और समर्थन की उसी स्तर की गारंटी देना मुश्किल हो सकता है जो उन्होंने शादी के दौरान प्राप्त किया था।”

15. दूसरा, अदालत को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो घर रहने के लिए एक खुशहाल और प्यार करने वाली जगह है, वह दुख और पीड़ा का स्रोत बन जाता है, जहां साझेदारों को दुःख होता है। जब बच्चे होते हैं तो वे उक्त घटनाओं के सीधे शिकार हो जाते हैं, हालांकि विवाह टूटने में उनकी व्यावहारिक रूप से कोई भूमिका नहीं हो सकती है। वे एक अपूरणीय क्षति के लिए पर्याप्त हैं, विशेष रूप से जब दंपति आपस में झगड़ते हैं, तो वे उसके मनोवैज्ञानिक और मानसिक प्रभाव के बारे में बेपरवाह और बेपरवाह रहते हैं। 1982 में, यह

थ्रिटी होशी डोलिकुका बनाम होशियाम शावाक्षा डोलिकुका, (1982)

2 एस. सी. सी. 544 ने कहा:

885

एसएमटी। रूपा सोनी बनाम कमलनारायण सोनी [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 886

“29.... हालांकि, एक टूटे हुए घर में बच्चों को बताने के लिए एक अलग कहानी है। जब माता-पिता गिरते हैं और परेशान होने लगते हैं, तो घरेलू जीवन की शांति और खुशी समाप्त हो जाती है और बच्चे सबसे अधिक गलती करने वाले बन जाते हैं। यह वास्तव में दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि माता-पिता को इस बात का एहसास नहीं है कि वे आपस में खिलवाड़ करके अपने बच्चों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। पति और पत्नी मुख्य रूप से बच्चों को इस दुनिया में लाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं और निर्दोष बच्चे अपने पिता और मां के बीच किसी भी विवाद का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। मानव स्वभाव की सामान्य कमजोरियों वाले मनुष्य, जुनून, पूर्वाग्रह और कमजोरी से ऊपर उठने की स्थिति में नहीं हो सकते हैं। वास्तव में मन एक विशिष्ट स्थान है और मानव मन की कार्यप्रणाली अक्सर अस्पष्ट होती है। दुर्भाग्य से कई कारणों से पति और पत्नी के लिए एक साथ रहना संभव नहीं हो सकता है और उन्हें अलग होने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हालांकि, कोई भी पति और

पत्नी जिनके बीच अपरिवर्तनीय मतभेद हैं, जो उन्हें अलग होने के लिए मजबूर करते हैं, उन्हें यह समझने और सराहना करने के लिए पर्याप्त समझ होनी चाहिए कि उनके बच्चों के प्रति उनके कर्तव्य हैं। जिन बच्चों को वे अस्तित्व में लाए हैं और जो निर्दोष हैं, उनके हित में प्रत्येक पति और पत्नी को अपने अलग-अलग अनुभवों की रचना करने का प्रयास करना चाहिए। यहां तक कि जब कोई पति और पत्नी अपने मतभेदों को सुलझा लेने की स्थिति में नहीं होते हैं और अलग होने के लिए मजबूर होते हैं, तो उन्हें इस तरह से अलग होना चाहिए जिससे बच्चों को कम से कम परेशानी हो।

(जोर दिया गया) 16। तथ्यों पर हमारे पास कहने के लिए बहुत कम है, विशेष रूप से बार में विद्वान वकीलों को सुनने पर। वे अपने लिए बोलते हैं। यह शादी वर्ष 2002 में संपन्न हुई थी। उनके बच्चे के जन्म के बाद मौसम खराब हो गया। 2006 से दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गए। अपीलार्थी-पत्नी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498 ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत शिकायत दर्ज की। प्रत्यर्थी-पति ने अपीलार्थी-पत्नी के चरित्र पर सवाल उठाया था। तलाक के लिए याचिका में काउंटर अफि डेविट फाई के नेतृत्व में एक याचिका भी ली गई थी। संयोग से, यह तर्क दिया गया था कि यह वह थी जिसने वैवाहिक घर को नष्ट कर दिया था। प्रत्यर्थी-पति ने अपीलार्थी-पत्नी की चिकित्सा जांच की भी मांग की, यह आरोप लगाते हुए कि वह व्यभिचार में रह रही थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया था।

### सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

गैर-शराब की अवधि के दौरान बच्चा। उक्त अनुरोध को उच्च न्यायालय के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था।

17. डेढ़ दशक से पार्टियां अलग-अलग रह रही हैं। जैसा कि बार में निष्पक्ष रूप से कहा गया है, विवाह अब और नहीं रहता है, और संबंध को तलाक के औपचारिक फरमान के अलावा समाप्त कर दिया गया था। इस अदालत से मंजूरी का इंतजार करते हुए यथास्थिति बनी हुई है।

18. उपरोक्त तथ्य निश्चित रूप से तलाक के लिए एक मामला बनाते हैं और इस प्रकार, शिल्पा में इस अदालत की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात।

शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन, 2023 (6) स्केल 402 लागू होगा।

सभी चौकों पर: “26. वी. भगत बनाम डी. भगत [(1994) 1 एस. सी. सी. 337], जिसे एन. जी. दास्ताने [(1975) 2 एस. सी. सी. 326] में निर्णय के 18 साल बाद 1993 में घोषित किया गया था, 'क्रूरता' शब्द को जीवन जैसा विस्तार देता है। यह मामला एक ऐसे पति के बीच था जो लगभग 55 वर्ष की आयु में एक अधिवक्ता के रूप में काम कर रहा था, और पत्नी, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में उपाध्यक्ष थी, जिसकी आयु लगभग 50 वर्ष थी, जिसके दो वयस्क बच्चे थे-पेशे से एक डॉक्टर और विदेश में काम करने वाले एक एमबीए डिग्री धारक। एक-दूसरे के खिलाफ जीवन के व्यभिचारी पाठ्यक्रम, मानसिक संतुलन की कमी और रोगजनक रूप से संदिग्ध चरित्र के आरोप

लगाए गए थे। इस अदालत ने देखा कि तलाक की याचिका आठ साल से अधिक समय से लंबित थी, और इस अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद, ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (1) (आई-ए) के तहत विचार की गई क्रूरता मानसिक और शारीरिक दोनों है, हालांकि क्रूरता क्या है, इसकी व्यापक अवज्ञा सबसे कठिन पंथ होगा। बचाव करने वाले पति या पत्नी के ज्ञान और इरादे, उनके आचरण की प्रकृति, पति या पत्नी के चरित्र और शारीरिक या मानसिक कमजोरी आदि पर बहुत कुछ निर्भर करता है। निंदनीय आचरण या वैवाहिक दयालुता के सामान्य मानकों से प्रस्थान का योग जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, या इसकी आशंका का कारण बनता है, क्रूरता का गठन करता है। लेकिन इन कारकों को स्वभाव और अन्य सभी विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि जिस आचरण की शिकायत की गई है वह ऐसा है कि याचिकाकर्ता को इसे सहन करने के लिए नहीं बुलाया जाना चाहिए। यह आगे विस्तार से बताया गया कि क्रूरता, मानसिक 887

एसएमटी। रूपा सोनी बनाम कमलनारायण सोनी [एम. एम. सुंदरेश, जे.] 888

या शारीरिक, जानबूझकर या अनजाने में दोनों हो सकते हैं। वैवाहिक दायित्व और जिम्मेदारियाँ डिग्री में भिन्न होती हैं। वे प्रत्येक घर में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग होते हैं, और कथित क्रूरता उस जीवन की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसके वे आदी हैं, या उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करती है। वे उस संस्कृति और मानवीय मूल्यों पर भी निर्भर हो सकते हैं जिन पर पति-पत्नी अपना महत्व निर्धारित करते हैं। दूसरे जीवनसाथी के अनजाने में लेकिन अक्षम्य आचरण से क्रूरता के उदाहरण हो सकते हैं। इस प्रकार, क्रूरता करने के इरादे और क्रूरता के वास्तविक कार्य के बीच एक अंतर है, क्योंकि इरादे की अनुपस्थिति, किसी दिए गए मामले में, कोई अंतर नहीं बना सकती है यदि शिकायत किए गए कार्य को अन्यथा क्रूर माना जाता है। इसलिए, जानबूझकर और जानबूझकर इरादे से कोई फर्क नहीं पड़ता। वी. भगत (ऊपर) के फैसले का पैराग्राफ 16 इस प्रकार है:

“16. धारा 13 (1) (आई-ए) में मानसिक क्रूरता को मोटे तौर पर उस आचरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो दूसरे पक्ष पर ऐसी मानसिक पीड़ा और घुटन पैदा करता है जिससे उस पक्ष के लिए दूसरे के साथ रहना संभव नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, मानसिक क्रूरता ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि पक्षों से उचित रूप से एक साथ रहने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि अन्यायपूर्ण पक्ष को इस तरह के आचरण को सहन करने और दूसरे पक्ष के साथ रहने के लिए उचित रूप से नहीं कहा जा सकता है। यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि मानसिक क्रूरता याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए है। इस तरह के निष्कर्ष पर पहुँचते समय, सामाजिक स्थिति, पक्षों के शैक्षिक स्तर, जिस समाज में वे चलते हैं, यदि वे पहले से ही अलग रह रहे हैं तो एक साथ रहने की संभावना या अन्यथा और अन्य सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए जिन्हें न तो संभव है और न ही पूरी तरह से निर्धारित करना वांछनीय है। एक मामले में जो क्रूरता है वह दूसरे मामले में क्रूरता नहीं हो सकती है। यह प्रत्येक मामले में उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया

जाने वाला मामला है। यदि यह आरोपों और आरोपों का मामला है, तो जिस संदर्भ में वे लगाए गए थे, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।”

xxx

xxx

xxx

## सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 14 एस सी आर।

33. ऐसा कहने के बाद, हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस न्यायालय द्वारा विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक देना अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि एक विवेक है जिसका उपयोग बहुत सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करने वाले कई कारकों को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्षों के लिए 'पूर्ण न्याय' किया जाता है। यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय को पूरी तरह से आश्वस्त और संतुष्ट होना चाहिए कि विवाह पूरी तरह से अव्यवहारिक, भावनात्मक रूप से मृत और मोक्ष से परे है और इसलिए, विवाह का विघटन सही समाधान है और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। यह कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, तथ्यात्मक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए। इसके लिए कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए जैसे कि विवाह के बाद पक्षों ने कब सहवास किया था; जब पक्षों ने आखिरी बार सहवास किया था; एक-दूसरे और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति; समय-समय पर कानूनी कार्यवाही में पारित आदेश, व्यक्तिगत संबंधों पर संचयी प्रभाव; क्या, और अदालत के हस्तक्षेप से या मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने के लिए कितने प्रयास किए गए थे, और अंतिम प्रयास कब किया गया था, आदि। अलगाव की अवधि पर्याप्त रूप से लंबी होनी चाहिए, और छह साल या उससे अधिक की कोई भी चीज एक प्रासंगिक कारक होगी। लेकिन इन तथ्यों का मूल्यांकन पक्षकारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, जिसमें उनकी शैक्षिक योग्यता, क्या पक्षकारों के कोई बच्चे हैं, उनकी उम्र, शैक्षिक योग्यता, और क्या अन्य जीवनसाथी और बच्चे निर्भर हैं, किस स्थिति में तलाक चाहने वाला पक्ष जीवनसाथी या बच्चों की देखभाल और व्यवस्था करने का इरादा रखता है। नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा और कल्याण का प्रश्न, पत्नी के लिए उचित और पर्याप्त गुजारा भत्ता का प्रावधान, और बच्चों के आर्थिक अधिकार और अन्य लंबित मामले, यदि कोई हों, प्रासंगिक विचार हैं। हम कारकों को संहिताबद्ध नहीं करना चाहेंगे ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को रोका जा सके। उल्लिखित कुछ कारकों को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है, और विचार करने योग्य है।”

19. निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने तलाक की डिक्री को अस्वीकार करने में एक अति-तकनीकी और पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया। ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी-पति अपीलार्थी-पत्नी के

साथ रहने के लिए तैयार है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप उतने ही गंभीर हैं जितने 889 में लगाए गए आरोप।

एसएमटी। रूपा सोनी बनाम कमलनारायण सोनी [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

उसके खिलाफ। दोनों पक्ष चले गए हैं और अपने-अपने जीवन में बस गए हैं। उनके साथ रहने के बिना केवल एक स्थिति की पीड़ा को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

20. उपरोक्त कारणों से, हम निचली अदालत के फैसले को दरकिनार करने के इच्छुक हैं जैसा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एफ. ए. में कहा था। (एम) 2011 की सं. 115। तदनुसार, उन्हें अलग कर दिया जाता है और तलाक की डिक्री देकर अपील की अनुमति दी जाती है।

21. कोई लागत नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान